भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1742
बुधवार, 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

नीली अर्थव्यवस्था संबंधी नीति

1742. श्री राजा अमरेश्वर नाईक::
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्री विनोद कुमार सोनकर:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री भोला सिंह:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में नीली अर्थव्यवस्था संबंधी नीति को अंतिम रूप दे दिया है और इसे शुरू करने के लिए तैयार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय नीली अर्थव्यवस्था परिषद बनाने के लिए तैयार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) प्रमुख हितधारकों और राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर 'स्वच्छ पृथ्वी, स्वच्छ सागर' की दिशा में क्या प्रगति हुई है; और
(च) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) जी, हाँ। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय देश के लिए समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था संबंधी राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दे रहा है।

(ख) भारत की समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था पर एक मसौदा नीति रूपरेखा तैयार की गई है। समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था नीति के मसौदा में तटीय क्षेत्रों के सतत विकास के लिए समुद्री क्षेत्र के सभी सेक्टररों (सजीव, निर्जीव संसाधनों, पर्यटन, समुद्री ऊर्जाआदि) के इष्टतम उपयोग की परिकल्पना की गई है। इस नीति दस्तावेज़ में समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था और समुद्री प्रशासन के लिए राष्ट्रीय लेखा रूपरेखा, तटीय समुद्री स्थानिक योजना और पर्यटन प्राथमिकता, समुद्री मत्स्यन, मत्स्य पालन और मत्स्य प्रसंस्करण, विनिर्माण, उभरते उद्योगों, व्यापार, प्रौद्योगिकी, सेवाएं और कौशल विकास, रसद, बुनियादी ढांचा और नौवहन, तटीय और गहरे समुद्र में खनन तथा अपतट ऊर्जा और सुरक्षा, रणनीतिक आयामों और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव के संबंध में प्रमुख सिफारिशें शामिल हैं। ।

(ग) जी, हाँ। प्रस्तावित राष्ट्रीय समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था सलाहकार परिषद (बीईएसी) में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव सदस्य होंगे। इसमें तटीय राज्यों के मुख्य सचिव/प्रधान सचिव और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

(घ) मसौदा नीति दस्तावेज आम जनता और सभी संबंधित हितधारकों से टिप्पणियों और प्रतिक्रिया के लिए रखा गया था। मंत्रालयों/विभागों, संसद सदस्यों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), उद्योग के प्रतिनिधियों और आम जनता से प्राप्त हुए अनेक मूल्यवान टिप्पणियों/सुझावों पर विचार किया गया है और नीति दस्तावेज को तदनुसार संशोधित किया गया है।

(ड.) 'स्वच्छ पृथ्वी, स्वच्छ सागर' नाम से कोई कार्यक्रम नहीं है। तथापि, 'स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर' नामक एक कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। यह तटीय जिलों के समानांतर कम से कम 75 समुद्र तटों की सफाई के लिए 75 दिनों की अवधि का तटीय सफाई अभियान है जो 5 जुलाई, 2022 को शुरू हुआ तथा जिसका समापन 17 सितंबर 2022 को 'अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस' पर होगा। यह कार्यक्रम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारतीय तटरक्षक, एमओईएफएंडसीसी, एमओवाईएएस, एनडीएमए पर्यावरण संरक्षण गतिविधि और सरकारी विभागों, स्वयंसेवी संगठनों, आम जनता एवं छात्रों के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।

(च) किए गए उपायों/नवीन पहलों में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पृथ्वी दिवस, समुद्र दिवस आदि के माध्यम से इन मुद्दों पर जागरूकता अभियान, प्रतियोगिताएं तथा कार्यशालाएं/संगोष्ठियां शामिल की जाएंगी।

*****